NAME OF THE NEWSPAPER दैनिक भास्कर DATE: - 3 AUG 2012

जवाब मांगते हैं कुछ अहम सवाल

पुण्य प्रसून वाजपेयी

जो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून की मांग करते हुए जंतर-मंतर से शुरू हुई, अब वही उसी जंतर-मंतर से भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक जंग का रूप ले चुकी है। तो, क्या वाकई अन्ना हजारे राजनीतिक विकल्प देने को तैयार हैं? और क्या वे चुनावी राजनीति की उस व्यवस्था को तोड़ पाएंगे जो धन-बल और जाति-धर्म के समीकरणों के सहारे कायम है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों को उठा रहा है और मौजूदा दौर में भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह सरकार नतमस्तक है, उसकी एक बड़ी वजह राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष की वह धारा है जिसने नवउदारवाद या फिर लूट की अर्थव्यवस्था की तरफ से आंख मूंद कर चुनावी जीत-हार को ही राजनीति का मूलमंत्र मान लिया है। सीधे कहें तो जनता पार्टी के प्रयोग के फेल होने के बाद राजनीतिक आंदोलनों की गोलबंदी के प्रयासों को सत्तालोलुपता से जोड़ दिया गया। और मंडल आयोग के लागू होने के बाद सामाजिक संघर्ष राजनीतिक लाभ पाने में खो गया। मंडल से निकले जातिगत समीकरणों के चुनावी दायरे में कभी आर्थिक सुधार के वे मुद्दे नहीं आए, जो दिल्ली से तय होते हैं और गांव को शहर में तब्दील करने और विकास के नाम पर खेती की जमीन को भी हड़प लेते हैं।

राजनीतिक तौर पर बीते बीस बरस में कभी कोई चुनाव इस आधार पर लड़ा ही नहीं गया कि जिस अर्थव्यवस्था को देश की नींव बनाई जा रही है, वह गांवों को कंगाल क्यों बना रही है। अन्ना हजारे राजनीतिक विकल्प का सवाल उठाते हुए पहली बार कुछ नए संकेत दे रहे हैं, जो मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों को चुनौती देता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के जरिए ग्रामसभाओं को दिल्ली के निर्णय में दखल देने के सवाल को अन्ना जिस तरीके से उठा रहे हैं, वह एक नई राजनीतिक लकीर है। दरअसल विकास की चकाचौंध के लिए पहली जरूरत जमीन की है और जमीन का मतलब है खेती की जमीन यानी किसानों को मजदूर में बदलने की सोच। टीम अन्ना जब हर ग्रामसभा को यह अधिकार देना चाहती है कि जमीन के अधिग्रहण का निर्णय वही ले तो इसका मतलब साफ है कि अन्ना की राजनीति वर्तमान संसदीय चुनावी धारा को 180 डिग्री घुमा देना चाहती है। असली सवाल यही है कि क्या जंतर-मंतर से वाकई राजनीतिक विकल्प की वह धारा निकल पाएगी जो मौजूदा संसदीय राजनीति के तौर-तरीकों को बदल दे? वजह यह कि ऐसे प्रयास इससे पहले कभी कारगर नहीं हो पाए हैं, जहां चुनी हुई सरकार को जनता के सेवक के तौर पर काम करने की दिशा में यह कहते हुए ले जाया जा रहा है कि यही संविधान का असली उद्देश्य है। अन्ना आंदोलन संविधान को ही अपना घोषणापत्र मान कर काम कर रहा है। यानी अलग से कोई ऐलान करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लोकतंत्र के अर्थ को ही अन्ना परिभाषित कर रहे हैं क्योंकि वे जो राजनीतिक लकीर खींच रहे हैं, उसके दायरे में किसान, मजदूरों के सवाल हैं। देश की खनिज संपदा के लूट के सवाल हैं। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाले संस्थानों के भ्रष्ट होने के सवाल हैं। यानी पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी की राजनीति का सवाल खड़ा होता है।

ये सवाल वोटरों की ईमानदारी और चुनावी राजनीति से मिलने वाली सत्ता की ईमानदारी से आगे के हैं। क्या राजनीतिक विकल्प की सोच इस ईमानदारी को चुनावी लड़ाई में मान्यता दिला सकेगी क्योंकि ईमानदार चुनावी प्रयास जमानत जब्त भी करवाता है। मावलंकर ने तो पोस्टकार्ड के जरिए वोटरों को अपनी ईमानदारी से चुनाव लड़ने का सच बताया, लेकिन गुजरात में वे हार गए। जनरल एसके सिन्हा आर्मी चीफ न बनाए जाने पर 1984 में पटना से चुनाव मैदान में खड़े हुए, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन 1957 में पटना में नामी अर्थशास्त्री और समाजवादी डॉ. ज्ञानचंद की जमानत पटना के बाकरगंज इलाके में पंसारी की दुकान चलाने वाले रामशरण साहू ने जब्त करवा दी थी। यानी, राजनीतिक विकल्प सिर्फ चुनावी जीत से तय नहीं हो सकता, बल्कि समाज के भीतर उन आकांक्षाओं को बदलने से तय होगा, जिसे राजनीतिक सत्ता के जरिए ही इस तरह जगाया गया है, जहां सत्ता पाना या सत्ता की मलाई भर मिल जाने में ही जीवन तृप्त माना जाने लगा है।

ऐसे में अन्ना के सामने जंतर-मंतर से आगे का रास्ता सिर्फ राजनीतिक पार्टी बनाने या ईमानदार उम्मीदवारों को खोजने भर का नहीं है बल्कि राजनीतिक तौर पर मौजूदा परिस्थितियों से उस जनता को जोड़ने का भी है जो हाशिए पर है। इसलिए अन्ना हजारे के देश नवनिर्माण पार्टी (अगर यह पार्टी का नाम हो तो) का काम महात्मा गांधी और विनोबा भावे के सपने को जगाना भी है और जेपी की अधूरी संपूर्ण क्रांति और मंडल आयोग से पैदा हुई सियासी राजनीति को आगे ले जाकर उस आर्थिक सुधार को चुनौती देनी है, जिसकी विसंगतियों से पूरा देश आहत है लेकिन किसी राजनीतिक दल के पास उसका कोई विकल्प नहीं है।

punyaprasun@gmail.com